DR. GYAN PRAKASH PILANIA (Rajasthan) : Sir, would you kindly permit me on one point of information? More details can be had from the CBI office and from the Home Secretary whose statements I had read myself.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no. It is okay. Now, Mr. Moinul Hassan.

Demand to commemorate the martyrdom centenary in memory of Madan Lal Dhingra, a great freedom fighter

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Sir, I would like to draw the attention of the Government to the need to commemorate the upcoming martyrdom centenary of the Indian political activist, Madan Lal Dhingra on August 17, this year.

Madan Lal Dhingra, a brave youngman and freedom fighter, was executed in London on August 17, 1909, after he assassinated a British official, Curzon Wyllie. The incident took place a hundred years ago, but it is a significant part of the Indian Freedom Struggle.

Madan Lal Dhingra was born in 1883 to a prosperous Hindu family in the province of Punjab. Later, he went to England for higher studies, took admission in engineering and became involved in the Indian Freedom Struggle.

He shot Wyllie who was notorious for using the Indians to serve as informers for the British in England. After one-and-a-half months trial, he was executed on August 17, 1909.

I urge upon the Government to take interest to get this event commemorated at the highest level, particularly in the educational institutions, to make our students more acquainted with the heroes of the Freedom Struggle and to arouse patriotic feelings among them. Thank you.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Demand to take speedy action on the pending matter of families of Kargil martyrs

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा विशेष उल्लेख कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों के लंबित मामलों पर शीघ्र कार्यवाही करने के बारे में है। महोदय, केन्द्र सरकार ने आपरेशन विजय, 1999 में पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध की गई कार्यवाही के दौरान मातृभूमि की रक्षा करते हुए, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनके परिवार के लोगों के लिए पेट्रोल पंप, नौकरियां तथा भूमि आबंटन का कार्य बहुत हद तक किया है और कारगिल में शहीद हुए जवानों के परिवारों के लोग आज अपना जीवन-यापन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ मामले है, जिनमें केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार का ध्यान समय-समय पर आकर्षित किया गया है, पर किन्ही कारणों से पिछले 3-4 वर्षों मे उन प्रकरणों की कोई पूछ-परख नही हो पाई है।

ऐसा ही एक मामला लांस हवलदार लक्ष्मन सिंह, क्रमांक 3171385 का है। थल सेनाध्यक्ष, जनरल वेद मलिक ने मरणोपरांत उनकी पत्नी श्रीमती शकुंतला देवी को नई दिल्ली में 16 दिसम्बर, 1999 को पदक दिया था। श्रीमती शकुंतला देवी ने अपने पुत्र पवन कुमार को घोषणा के अनुरूप नौकरी दिलाने के लिए रेल मंत्रालय में वर्ष 2006 में

आवेदन दिया था, जो अभी तक लंबित है। इसके परिणामस्वरूप श्रीमती शकुंतला देवी कठिनाइयों के दौर से गुजर रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस प्रकार के प्रकरणों की ओर विशेष ध्यान दे, ताकि उनका शीघ्र निराकरण हो सके।

Demands to give priority to the issues pertaining to SCs and STs

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak. In the recent past, there is no focus or priority for the issues concerning the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in particular. There are two constitutional Commissions for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes but their reports are not discussed in the Parliament. The first UPA Government had assured about affirmative actions, reservations in private sector and the Reservation Act too. No progress, whatsoever has been made in these matters. The hon. Prime Minister in his speech to the National Development Council during June 2005, wanted to remove the gap between the Scheduled Castes and other sections within 10 years. For this, the Planning Commission has also issued many guidelines for S.C.S.P. and T.S.P. However, there is no progress, and there are no reports on the matter.

Hon. Minister for Social Justice and Empowerment should enlighten the House on all these issues. Thank you, Sir.

Demand for solving problems being faced by workers in getting payment of wages under NREGA

सुश्री अनुसुइया उइके (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन एवं केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर दिलाला चाहती हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों को वर्ष 100 दिवस का रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है तथा मजदूरी का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते से संबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा जमा किया जाना है।

भुगतान की यह व्यवस्था अच्छी है, किन्तु इसका दूसरा पक्ष यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों बैंकर्स द्वारा मजदूर का खाता खोलने में हीला-हवाला किया जाता है। जिसके कारण मजदूरों के भुगतान में छह माह से लेकर एक वर्ष तक का विलंब हो रहा है। मजदूरों के समक्ष भूखों मरने की नौबत आ गई है। एक ओर 100 दिवस का कार्य देना है, वही दूसरी ओर 200 से 350 दिन तक मजदूरी नहीं दी जा रही है, जिसका एक मात्र कारण बैंकों द्वारा खाता नही खोलना है।

इस संबंध में जब कलेक्टर को सूचित किया जाता है, तो वे भी भुगतान कराने में असमर्थ होते है, क्योंकि कलेक्टर का बैंकर्स पर सीधा कोई नियंत्रण नहीं है। यदि बैंकर्स पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर को अधिकार दिया जाए, तो इस योजना के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कराने मे सुविधा होगी।

अतएव, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मजदूरों को मजदूरी दिलाने, भूखों मरने से बचाने तथा योजना के मूल उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कलेक्टर को बैंकर्स पर नियंत्रण के लिए प्रभावी बनाया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you, Miss Uikey. Shri Prabhat Jha. He is not here. Dr. T. Subbarami Reddy. He is also not here. Miss Mabel Rebello. She is not here. Now, Shri Krishan Lal Balmiki.